INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

भारत की सामाजिक–आर्थिक राजनीतिक समस्या का कर्तव्यबोध (गॉधी व अम्बेडकर चिन्तन प्रासंगिक)

संजय कुमार शर्मा
शोधार्थी
सिक्किम स्किल विश्वविद्यालय,
सिक्किम
एवं
यतीक कुमार शर्मा
शोधार्थी
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

डॉ. हंस कुमार शर्मा
प्राचार्य
श्री वीर तेजाजी महाविद्यालय, राडावास
शाहपुरा जिला जयपुर राज.
मो.नं. 8209973989
Mail: dr.hanskumar7272@gmail.com

ब्रिटिश साम्राज्यवाद 17वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी (जिसने 1688ई. की रक्तहीन या गौरवपूर्ण क्रान्ति से व्हिग कुलीन तंत्र का विशिष्ठ एकाधिकार पाया था) ने सुदूर पूर्व व मध्य अफ्रीका के समुद्र पार देशों के माल व उत्पादन व्यापार का एकाधिकार प्रपत्र (चार्टर)प्राप्त कर लिया। उपरोक्त कम्पनी का उद्देश्य "ब्रिटिश उत्पादकों के लिए बाजार ढूँढना नहीं वरन इंग्लैण्ड व यूरोप के तैयार बाजार के लिए भारत व भारत के पूर्व देशों में उत्पादित माल, विशेषतया मसाला, कपडा, रेशमी माल की निरन्तर व सुरक्षित पूर्ति बनाये रखना था। इन सफल अभिचरणें का उद्देश्य पूर्ति के बदले भारी मुनाफा कमाना था। कुल ही दिनों के ब्रिटिश साम्राजयवाद का तेजी के साथ विकास हुआ और **"श्वेत प्रवासियों का उपनिवेश"** तथा 'शोषण के लिए उपनिवेश' नामक दो साम्राजयों का जन्म हुआ। इंग्लैण्ड की राजनीति में इन श्वेत व अश्वेत साम्राज्यों ने मूलतः भिन्न भूमिकाऐं निभायी। जबकि कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड व दक्षिण अफ्रिका आदि श्वेत उपनिवेशों को अंग्रेजी सरकार, प्रेस व जनता द्वारा विशेष व्यवहार मिला, अफ्रीका व एशिया के काले देशों को आर्थिक शोषण व राजनीतिक दमन के लिए उर्वर भूमि समझा गया। भारत का स्थान द्वितीय श्रेणी में आता है, जैसा लार्ड कर्जन ने 1905 में कहा था, जहॉ शोषण व प्रशासन का चोली दामन का साथ है।"

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास 18वीं सदी के मुगल साम्राज्य के पतन के समय से प्रारम्भ होकर वर्तमान सदी के मध्य में स्वतन्त्रता प्राप्ति तक करीब 200 वर्षो तक फैला हुआ है। इस विस्तृत काल को तीन भागों में बांटा जा सकता है। 1. प्रथमकाल – मुगल साम्राज्य के अन्तिम दिनों से उन्नीसवी सदी के प्रथम दशक तक '**पूँजी की भूमिका का काल'**; इसे डेस्ट इण्डिया कम्पनी के आर्थिक अन्वेषण और एकाधिकारी व्यापार के लिए क्षेत्रीय अधिकरण का काल भी कहा जाता है। द्वितीय काल 1813 से 1857 तक का है, जब इंग्लैण्ड की मुक्त व्यापार पूँजी ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस काल में कम्पनी के स्वामियों तथा अंग्रेजी शासन के नियन्ताओं के

हितों के समन्वय के लिए कुछ संवैधानिक सुधार भी किये गये। तृतीय व अन्तिम काल 1858 से 1847 तक का है। यह सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसमें अंग्रेजी वित्त–पूँजी का भारतीय स्वाधिनता आन्दोलन से आमना–सामना हुआ। वर्तमान भारतीय एवं तटवर्ती इतिहास के उर्वाकाल में देश एस उपनिवेशवाद से एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप मे तदनुसार ब्रिटिश कामनवेल्थ के एक स्वतन्त्र सदस्य के रूप में उभर कर सामने आया।

साम्राज्यवाद– राजनीतिक अधीनता व आर्थिक शोषण के लिए विकसित राष्ट्रों की राजनीति व आर्थिक शक्तियों का विकास विश्व के पिछडे देशों के विस्तार मे सिद्धान्त के मुख्य कथनः–

1. मूनः प्रजातीय विभेदों के कारको पर बल
2. बियर्डः मात्र आर्थिक शोषण के लिए शासन द्वारा अन्य क्षेत्रों के अधिग्रहण व प्रभाव क्षेत्र के विस्तार पर बल
3. बॉनः मात्रात्मक पैमाना पर बल जिसमें छोटे साम्राज्यवाद को शामिल नहीं किया जाता है।
4. मामैन्थाऊः राज्य शक्ति का अपनी सीमाओं से बाहर विस्तार जिसमें मात्रात्मक पैमाने के स्थान न होने पर बल
5. शुपीटरः नव पूँजीवाद के विषय पर जोर
6. विन्स्ली : साम्राज्यवाद के क्रियान्वयन में संगठन व विशेष उद्देश्य पर बल
7. हॉबसनः आश्रितों के शुल्क के लिये राज्य शक्ति का विस्तार और उसमें आर्थिक कारण की निर्णायक भूमिका पर बल

निर्यात पूँजी तथा इसके तीन निष्कर्ष हैः–

1. औपनिवेशिक जनता का शोषण होता है, जब कष्टों की वृद्धि होती है एवं पतन में पूँजीवादी नियम के अन्तर्गत उनकी स्वतन्त्रता कूचल दी जाती है।
2. राष्ट्रों के मध्य तेजी से युद्धों का जन्म होता है क्योंकि देश के भीतर बाजारों व क्षेत्रों की खोज में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में व शक्ति संगठनों व गठजोडों के मध्य संघर्ष के परिणाम स्वरूप युद्ध अनिवार्य हो जाता है और
3. पूँजीवाद का अन्त व नयी व्यवस्था का उदय होता है जब श्रमिकों के युद्ध में सैन्य शिक्षण जो राष्ट्रीय युदों के रूप में शुरू होता है तब युदों में परिवर्तित हो जाता है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् मित्र राष्ट्रों द्वारा समय–समय संयुक्त राष्ट्रसंघ का गठन हुआ एवं पूँजीवाद के रूप में अमेरिका व साम्यवादी विचारक के रूप में रूस द्वारा 'बारसापैक्ट' एवं नाटो संगठन बनाया एवं नवविकासशील स्वतन्त्र राष्ट्र एवं भारत द्वारा गूटनिरपेक्षता का गठन करके 'तटस्थता की नीति' उद्देश्य बना रहा एवं पूर्वी एशिया, पं. एशिया व यूरोप व अन्य पश्चिमी राष्ट्रों ने व्यापार एवं व्यवसाय में सोहार्द्धपूर्ण व्यवहार हेतु छोटे–छोटे गठन किये गये उसी संदर्भ में चीन की विस्तारवादी नीति एवं हिन्द महासागर में व्यापार व व्यवसाय हेतु पश्चिमी

राष्ट्रों द्वारा नयी कूटनीति व दबाव बनाये रखने से भारत एवं पडौसी राष्ट्रों के भी सार्क का गठन किया गया।

सार्क (दक्षेस) का पूरा नाम साऊथ ऐसासिएशन फॉर रीजनल को–ऑपरेशन अर्थात ''दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 7 व 8 दिसम्बर, 1985 को ढांका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा 'सार्क' की स्थापना हुई। ये देश है– भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीप एवं 12–13 नवम्बर,2005 को बांग्लादेश की राजधानी ढांका में सम्पन्न हुए 13वें शिखर सम्मेलन में 'अफगानिस्तान' को इस संगठन का आठवा सदस्य देश बनाया गया है। वर्तमान में 8 सदस्य है।

सार्क वार्षिक शिखर सम्मेलन क्रमशः–

1– बांग्लादेश : अ–1985 (7–8 दिसम्बर) ढांका बांग्लादेश में व ब– 10–11 अप्रेल 1993, स– 13वॉ 12–13 नवम्बर 2020, अन्य रहे है।

2– भारतः 1986 बैंगलोर , 1995 नई दिल्ली, 14वॉ 2007 नई दिल्ली

3– नेपालः तीसरा 1987 (काठमाण्डु), ग्यारहवा 2002, अठ्ठारवा 2014 में रहा है।

4– पाकिस्तानः चतुर्थ 1988 इस्लामाबाद, बारहा 2004

5– मालद्वीपः पॉचवा 1991 माले, नौ वॉ 1997, सतरहवा 2011 अडडु

6– श्रीलंकाः छठा 1991 कोलम्बो, दसवा 1998, पन्द्रबा 2008

7– भूटानः सौलहवा 2010, 28–29 अप्रेल (थिम्पू)

मालद्वीप को छोडकर संघ के शेष सदस्य भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से है। ये सभी देश इतिहास, भूगोल, धर्म, और संस्कृति के द्वारा एक–दूसरे से जुडे हुऐ है विभाजन के पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही प्रशासन और अर्थव्यवस्था के अभीन्न अंग थे, लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात् ये देश एक–दूसरे से दूर हो गऐ। सार्क का मुख्यालय सचिवालय काठमाण्डू (नेपाल) में है तथा संगठन के वर्तमान महासचिव अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में 02 वर्ष सदस्य राज्य मनोनीत करता है। सार्क (सचिवालय) की स्थापना 16 जनवरी 1987 को की गई थी प्रतिवर्ष 08 दिसम्बर को सार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है।

सार्क संगठन द्वारा शान्ति, विकास, गरीबी उन्मूलन और क्षेत्रीय सहयोग संगठन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सार्क क्षेत्र के व्यक्तियों व संस्थाओं के लिए पुरस्कार व सम्मान पदक स्थापित किया गया है।

– **सार्क वर्ष/दशक**– 1989 मादक पदार्थ विरोधी अभियान, 1990 बालिका वर्ष, 1991 आश्रय वर्ष, 1992 पर्यावरण वर्ष, 1993 विकलांग वर्ष, 1994 युवा वर्ष, 1995 गरीबी उन्मूलन वर्ष, 1996 साक्षरता वर्ष, 1997 शासन में भागीदारी वर्ष, 1991–2000 दहेज बालिका दशक, 2005 पर्यटन वर्ष, 2006–2015 गरीबी उन्मूलन दशक ।

– **सहयोग क्षेत्रों का निर्धारण**– सार्क का मूल आधार क्षे.ीय सहयोग पर बल देता है। अगस्त 1983 में क्षेत्रीय सहयोग के ऐसे 09 क्षेत्र रेखांकित किए गये थे– कृषि, स्वास्थ्य सेवाऐं, मौसम विज्ञान, डाक–तार सेवाऐं, ग्रामीण विकास, विज्ञान व तकनीकी, दूर संचार तथा यातायात, खेलकूद तथा सांस्कृतिक सहयोग, दो वर्ष पश्चात् ढाका में इस सूचि में कुछ और विषम जोड दिए गये– आतंकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी तथा क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका व आत्मनिर्भरता हेतु अथक प्रयास किये जा रहे है।

सार्क के 7वें शिखर सम्मेलन में ढाका अप्रेल 1993 में साप्टा जिसे दिसम्बर 1995 में लागू किया गया दक्षिण एशिया वरियता व्यापार सम्मेलन, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग बढाने में प्रयास करता है। उसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2005 तक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा का निर्माण करना था।

सार्क का चार्टर एवं ढाका घोषणा– इसमें 10 धाराऐं (अनुच्छेद) है इनमें सार्क के उद्देश्यों, सिद्धान्तों, संस्थाओं तथा वित्तिय व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है। जिसमें दक्षिण एशिया खेत्र की जनता के कल्याण, जीवन स्तर में सुधार, सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना रहा है वहीं पर आपसी सुझावानुसार .तथा आपसी समस्याओं को सुलझाना एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना एवं अन्य विकासशील देशो के साथ सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना तथा सामान्य हित के मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना रहा है।

सार्क का 14वॉ शिखर सम्मलेन 3–4 अप्रेल 2007 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ यह सम्मेलन कई मायनों में विशिष्ठ रहा। एक ओर अफगानिस्तान 08–बराबर दूसरी ओर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुऐ। इससे सार्क के देश भौगोलिक सामरिक दृष्टिकोण से कच्चे माल व उपजाऊ भूमिं, हिन्द महासागर के तटों पर स्थित रहने से ये महत्वपूर्ण व्यापार का तट बन्दरगाह रहे है जिसका 21वीं शताब्दी में भूमण्डलीकरण के क्रम में विकासशिल राष्ट्र का उत्तरोत्तर विकास एवं सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का समाधान, गॉधी चिन्तन में विकास का मार्ग समाहित है जिसमें श्रम प्रधानजीवन, स्वालम्बन, विकेन्द्रीकरण, कर्तव्य–भावना, अंत्योदय, ग्राम–स्वराज, विकास का मानवीकरण, दिशा रहित आर्थिक विकास हानिकारक, आदर्श गॉव, चरखा, ग्रामोधोग, तालीमी शिक्षा, स्वदेशी भावना व उधोग, आचरण के प्रतिमान, लोकतंत्र और पंचायती राज, कृषि एवं ग्रामीण विकास 'दृष्टीशिप' में यह भावना निहित है– अमीरी को मिटाना नहीं, स्वैच्छिक वितरण से गरीबी को मिटाना, अमीरों से छीनकर गरीबों में बांटना नहीं (यह द्वेष और संघर्ष का मार्ग है) अमीरों से लेकर गरीबों का स्तर उन्नत करना।''

पिछले कुछ दशकों में हमने गॉधी को खोकर बहुत कुछ खोया तो कुछ पाया भी है। विश्व के कुछ उन्नत कहे जाने वाले देशों में साम्यवाद का उत्थान व पतन, पूॅजीवाद का फैंलता

साम्राज्यवाद वही उपनिवेशवाद की समाप्ति पर उसका सिकुडना जिसमें उन्नति के शिखर और उनमें से उन्नत मानवता के धराशायी होते सपने भी, खुलापन 'भूमण्डलीकरण' पहले रूस, चीन और भारत की स्थिति अन्तर जिसमें 'ग्लास नोस्त' के पूर्व रूस की बाहरी खिडकिया बंद थी 'आयरन' कटेन का देश कहा जाता था। जब गोर्बाचोव ने खुलेपन का नारा दिया तो 'विखण्डन हो गया' नव औधोगिक देशः कोरिया, ताइवान, सिंगापुर की मिसाले सामने है उन्हें विकास का तोहफा अमरीका ने नहीं बल्कि उन्होंने अपनी नीतियों, श्रम निष्ठा, और उद्यम से हांसिल किया सबसे पहले जरूरी है परस्पर सकारात्मक सहयोग का रचनात्मक उपाय। मॉडल अमरीकी हो या जापानी यह हमारे उधम और चिंतन पर निर्भर है कि हम लातानी अमरीकी देशों की तरह विश्व बैंक व अन्तराष्ट्रीय मुद्राकोष ऋण को अपने गले का फंदा बना ले या अपने हित के उसका सही उपयोग कर ले। गॉधी ने कहा था "देश की सर्वसममत नीति देशहित में ही प्रभावी नहीं होती बाहर भी प्रभावी सिद्ध होती है।"

1948 के बाद शासन के स्थान में विधि द्वारा विकसित करने का संशोधन द्वारा प्रयास रहा है। इन्हें अनेक देशों ने अनुसमर्थन दिया है। क्रमशः (1) नामदार अपराध का दंड (1948), स्त्रियों के राजनीतिक अधिकार (1952), आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार (1966), नागरिक और राजनीतिक अधिकार (1966), युद्ध अपराध और मानव अपराधों पर राष्ट्रीय कानूनों द्वारा सीमा निर्धारण की अमान्यता (1968), नया विभेद के अपराध का दमन और उसे दंडित करना (1973) इत्यादि । विचित्र बात यह है कि मानवाधिकारों का विश्व भर में ढिंढोरा पीटने वाले देश अमरीका ने इनमें से किसी .का अनुसमर्थन नहीं किया है।

सभा में 25 नवम्बर, 1949 को कहा था कि "26 जनवरी, 1950 से देश के राजनीतिक संवन में समता का पदार्पण होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता बनी रहेगी। यदि यह असंगति कायम रही तो इस विषमता की आंच में झुलसा वर्ग हमारे महान् प्रयासों से निर्मित इस राजनीतिक महल को ध्वस्त किए बगैर नहीं रहेगा।" – असमानता से पीड़ित लोग राजनीतिक प्रजातन्त्र के ढांचे को उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए डॉ. अम्बेडकर ने राजनीतिक प्रजातन्त्र को यथार्थ बनाने हेतु सामाजिक और आर्थिक प्रजातन्त्र पर बल दिया है। डॉ. अम्बेडकर ने अपनी रचना 'स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटीज में लिखा है कि "जब तक आर्थिक संरक्षण नहीं है तब तक मूल अधिकारों का कोई महत्त् नहीं है। संसदीय लोकतन्त्र स्वयंमेव आर्थिक आदर्श प्राप्त नहीं कर सकता और तानाशाही से तभी बचा जा सकता है जबकि संसदीय लोकतन्त्र की परिधि में सरकारी समाजवाद का मार्ग अपनाया जाए ।"

सामाजिक प्रजातन्त्र जीवन की एक पद्धति है; इस पद्धति, सिद्धान्त या ढंग में स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारे (बन्धुत्व) के सिद्धान्तों को एक दूसरे से अलग–अलग करके नहीं देखा जाता, बल्कि तीनों को एक दूसरे का पूरक मानते हुए उन्हें समन्वित रूप में देखा जाता है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि "समानता के बिना स्वतन्त्रता से बहुसंख्यक पर थोड़ों की सर्वोच्चता

स्थापित हो जाएगी; स्वतन्त्रता के बिना समानता से व्यक्तिगत पेशकदमी की हत्या होगी; भाईचारे के बिना स्वतन्त्रता और समानता को नैसर्गिक प्रवाह प्राप्त नहीं होगा।"

डॉ. अम्बेडकर का कहना है कि अस्पृश्यता के निवारण के लिए जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन अनिवार्य है। उनका कहना हैं कि "जाति संस्था का नाश ही समानता का निर्माण है।" डॉ. अम्बेडकर ने जाति उन्मूलन के लिए ये सुझाव दिए हैं– (i) एक वर्णीय व्यवस्था; (ii) अन्तर्जातीय विवाहः (iii) पुरोहिताई के व्यवसाय का प्रजातन्त्रीकरण मध्यम वर्ग का रहा है।

डॉ. अम्बेडकर एक वकील, न्यायशास्त्री और संविधानवेत्ता थे। अतः वे सरकार की सत्ता और व्यक्ति की स्वतन्त्रता में सन्तुलन, सामाजिक शान्ति और जनता के विभिन्न वर्गों के बीच न्याय–व्यवहार के लिए विधि के शासन के महत्त्व को समझते थे। उनका मानना है कि विधि "समानता और स्वाधीनता की प्रहरी है। यह सरकार, समाज और राष्ट्र की समूची कार्यप्रणाली को नियन्त्रित करती है; यह सभी को सीमाओं में बांधती है।" विधि के सम्बन्ध में डॉ. अम्बेडकर की धारणा है कि उसे केवल दण्ड दे कर ही लागू नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि शिक्षा और सामाजिक भावना के आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

अंग्रेजों के विरूद्ध हमारी लम्बी व कठिन लडाई इसलिये रही थी, उन्होंने अपने हित में हमारे लघु व कुटीर उधोग नष्ट कर दिये, गरीबकों के रोजगार छीन लिये, उनकी भाषा, आस्था तक छीन ली। पूरी तरह नही उसका मुख्य कारण हमारी आस्थाओं की जडे बहुत गहरी रहीं है और परामुखी वे लोग जो शहरों की ओर पलायन करने लगे।

संविधान सभा–

महात्मा गांधी राजनीति विचार एवम् अम्बेडकर के विधि व आर्थिक विचार का सामाजिक समरसता में (तटस्था) मानव संसाधन का उत्तरोत्तर विकास वृद्धि का लक्ष्य व उद्देश्य समस्या समाधान (कर्तव्य व अधिकार) मुख्यतः योगदान प्रासंगिक रहा है। विपुल आर्थिक संसाधन व तकनिकी आयाम में महात्मा गांधी के राजनीति विचार डॉ. अम्बेडकर के विधि व आर्थिक कारण माना है।

सारांशतः अविकसित या विकासशील देश में समृद्ध पश्चिमी देशों की जीवन शैली प्रचिलत हो जाऐ तब साधन तो कुछ ही हाथों के लिए उपलब्ध होंगें फिर सूचना कान्ति से आम लोगों की आकांक्षाओ–अपेक्षाओं में टकराव और अपराध को रोकना असम्भव होगा, येन–केन प्रकारेण धन प्राप्ति की लालसा चोरी, धोखाधडी, अपराध, हिंसा के मार्ग रहा है, अतः हमें ट्रस्टीशिप सिद्धान्त से सम्भव है जहाँ खुलेपन की अर्थनीति से हमें उत्पादन और समृद्धि को बढाना है और उसका नीतियुक्त विवरण भी करना होगा। स्वदेशी भावना बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों के खिलाफ जनजागरण अभियान भी तभी जरूरत है जब हमारे छोटे उत्पादकों ओर कुटीर उधोगों का बाजार भी वृद्धि होने लगे, उक्त हेतु राज्याध्यक्षों की हत्याऐं करके सरकारों का तख्ता पलटने, अपने हानीकारक उत्पादों का असर जानने के लिए विकासशील व विकसित देशों की निर्दोष जनता को बलि का बकरा बनाने और अपने आणविक कचरे को पिछडे देशों में फेककर लोगों की जानों (हत्याओं)

से खेलों तक की अमानवीय भूमिका भी निभाई है। वर्तमान में सूचना माध्यमों के आकाशिय हमले द्वारा हमारी सदियों पुरानी आध्यात्मिक संस्कृति को ही भ्रष्ट अप संस्कृति में बदलने का प्रयास कर रही है। यही वह असली खतरा है जो हमें मानसिक गुलामी की ओर ढकेलने का संकेत दे रही है। इस सारी स्थितियों के संदर्भ में ही आज गाँधी की प्रासंगिकता बढी है जो सार्क देशों को संयम का अर्थ, 'स्वयं का दमन नहीं होता नैतिकता से रहित आर्थिक उन्नति कभी भी सही विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करती भारत एवं सार्क के देशों पर जहाँ भौतिक व मानसिक विकास को साथ–साथ प्रश्रम देकर मानव के समग्र विकास पर बल दिया गया है जो सामाजिक विकास व संचार साधनों के कारण माना है।

मानव विकास की स्थापना एवं आवश्यकता व माँग के आधार पर योजनाओं के लिए अनुदान दक्षिण एशिया में बड़े विकास बैंक की स्थापना की जा सकती है। जिससे चीन के विस्तार का प्रमुख कारण उसके विपुल आर्थिक संसाधन व तकनीकी रही है।

संदर्भ सूचीः–

1. डॉ.बी.एल. फडीयाः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2007
2. डॉ. कुलदीप फडीयाः अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, साहित्य प्रकाशन, आगरा, 2012
3. डॉ. जे.सी. जौहरी, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा.लि., नई दिल्ली, 2000
4. दैनिक समाचार–पत्र
5. डॉ. विरेन्द्र शर्मा, भारत के पुननिर्माण में गांधी जी का योगदान, श्री पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1984
6. राजी सिंद, रिलेवेन्स ऑफ गॉधीयन थॉट, क्लासिकल पब्लिशिंग कं., नई दिल्ली, 1983

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA

Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM